

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 918
दिनांक 25 जुलाई, 2023 के लिए प्रश्न

डीएचडी द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं

918. श्री दुर्गा दास उइके:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से मध्य प्रदेश में अब तक जनजातीय समुदायों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;
- (ख) बैंकों से ऋण प्राप्त करने में डीएचडी की क्या भूमिका है;
- (ग) सरकार के उद्देश्य के अनुसार, छोटे किसानों को उक्त योजना से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और
- (घ) विभाग द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) डीएचडी अनेक योजनाएं लागू कर रहा है जो जनजातीय समुदायों सहित सभी समुदायों के लिए लागू हैं। योजना-वार विवरण इस प्रकार है:

योजना का नाम	कवर किए गए जनजातीय लाभार्थियों की संख्या
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास, जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा तथा विद्युत चाफ कटर का वितरण	3150
राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनआईपी)	39,61,000
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)	1,50,10,187 कुल लाभार्थी (जनजातीय लाभार्थियों सहित)

(ख) डीएचडी प्रत्यक्ष रूप से ऋण के संवितरण/संस्वीकृति में शामिल नहीं है। हालांकि, विभिन्न योजनाओं में जहां योजना में ऋण की आवश्यकता होती है, लाभार्थी के लिए ऋण संस्वीकृति को सुगम बनाने के लिए ऋण देने वाली एजेंसियों के साथ उसकी नियमित निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ) विभाग द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और लाभ का विवरण इस प्रकार है:-

- **डेयरी विकास योजनाएं-** पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं:
 - (i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
 - (ii) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

- (iii) डेयरी कार्यकलापों में शामिल डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसीएफपीओ)

उपरोक्त योजनाएं लाभार्थी उन्मुख नहीं हैं। जहां इन योजनाओं से डेयरी मूल्य श्रृंखला अवसंरचना सृजित/सुदृढ़ की गई है, दूध उड़ेलने वाले ग्राम स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं।

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन और बोवाईनों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना देसी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की वृद्धि और देसी स्टॉक की बढ़ी हुई उपलब्धता में योगदान दे रही है और योजना को लाभ डेयरी में शामिल 8 करोड़ किसानों विशेषरूप से लघु और सीमांत किसान तथा भूमिहीन श्रमिकों को मिल रहा है। योजना के कार्यान्वयन तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों के कारण, देश में दूध उत्पादन 6.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 221 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2020-21 में दूध उत्पादन का मूल्य 9.32 लाख करोड़ रु. था जो खाद्यान्न उत्पादन के मूल्य से अधिक था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 50% से कम एआई कवरेज वाले 604 जिलों में किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की निःशुल्क प्रदायगी के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत अब तक 5.82 करोड़ पशुओं का गर्भाधान किया गया है, 7.26 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 3.81 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** उक्त योजना के रोजगार सृजन जैसे अनेक लाभ हैं जो छोटे किसानों को मिलते हैं।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण:**
 1. **टीकाकरण:**
 - 1.1 एफएमडी टीकाकरण (चरण-2)- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 24.18 करोड़ (94%) गोपशुओं और भैंसों का टीकाकरण करते हुए एफएमडी का चरण-1 बंद कर दिया है।
 - 1.2 एफएमडी टीकाकरण (चरण-3)- अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 11.29 करोड़ वैक्सीन खुराकों में से 4.89 करोड़ वैक्सीन खुराकों का उपयोग किया गया है। 6 राज्यों (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और दिल्ली) ने टीकाकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। वर्तमान में 6 राज्यों में टीकाकरण चल रहा है और 11 राज्यों को अभी भी टीकाकरण का चरण-3 शुरू करना है।
 - 1.3 ब्रूसेलोसिस- ब्रूसेलोसिस के लिए 2.25 करोड़ मादा बछियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
 - 1.4 पीपीआर- मिशन उत्कर्ष के 10 प्राथमिकता जिलों सहित 9 राज्यों को आपूर्ति की गई 2.85 करोड़ वैक्सीन खुराकों के मुकाबला 1.84 करोड़ भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
 - 1.5 सीएसएफ-26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई 59.57 लाख वैक्सीन खुराकों के मुकाबला 16.84 लाख सुअरों का टीकाकरण किया जा चुका है। 17 राज्यों ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है, शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी शुरू करना है।

योजना के तहत किया गया राज्य-वार टीकाकरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

2. मोबाइल पशुचिकित्सा इकाईयां:

किसानों के द्वार पर मोबाइल पशुचिकित्सा इकाईयों (एमवीयू) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है और देशभर में 4340 एमवीयू के लिए सहायता दी है तथा वर्ष 2021-22 से 682.85 करोड़ रु. जारी किए हैं।

वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान संस्वीकृत एमवीयू की राज्य-वार कुल सं. और जारी निधियां **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

1									
2	आंध्र प्रदेश	93.66	89.18	10.80	10.00	59.02	34.26	0.93	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.61	0.10	0.00	0.00	3.56	0.03
4	असम	0.00	0.00	13.72	5.68	0.00	0.00	10.78	1.50
5	बिहार	0.00	0.00	24.37	22.77	0.00	0.00	2.41	0.00
6	चंडीगढ़	0.19	0.19	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.58	4.49	4.54	4.14	4.57	3.46
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	1.38	1.29	0.18	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.42	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00
11	गुजरात	122.38	0.00	7.57	7.31	53.24	0.00	0.00	0.00
12	हरियाणा	0.00	0.00	5.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	18.51	13.52	3.75	0.98	0.00	0.00	0.02	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	25.66	0.00	4.77	1.02	4.31	4.30	0.00	0.00
15	झारखंड	0.00	0.00	11.40	7.20	0.00	0.00	5.67	0.00
16	कर्नाटक	98.53	100.71	10.00	9.49	90.08	87.99	3.24	2.53
17	केरल	14.43	12.27	2.53	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00
18	लद्दाख	0.68	0.00	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	159.52	0.00	45.10	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	169.38	160.33	29.07	10.49	2.58	2.52	0.14	0.02
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.44	0.16	0.02	0.02	2.35	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.94	0.12	0.00	0.00	4.25	0.32
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	1.12	0.29
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	3.64	0.19
26	ओडिशा	95.92	4.71	4.49	4.49	69.05	48.25	1.35	0.68

27	पुदुचेरी	0.67	0.50	0.09	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00
28	पंजाब	69.50	0.00	6.50	3.72	0.00	0.00	0.23	0.19
29	राजस्थान	50.13	0.00	25.55	0.00	2.68	2.68	1.09	0.70
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.25	0.05	0.00	0.00	0.25	0.12
31	तमिलनाडु	90.00	86.43	24.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
32	तेलंगाना	52.22	0.00	5.45	4.08	0.00	0.00	1.80	0.00
33	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.38	0.20	0.00	0.00	4.06	0.26
34	उत्तर प्रदेश	108.19	12.81	70.46	64.39	0.00	0.00	4.13	3.27
35	उत्तराखंड	20.33	7.26	3.86	1.71	0.00	0.00	0.16	0.10
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	22.27	21.56	0.00	0.00	3.20	3.17
	कुल	1,191.79	489.18	339.37	224.75	285.52	184.15	59.58	16.84

एमवीयू की राज्य-वार स्थिति

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत एमवीयू की सं. (खरीद और अनुकूलन)	एमवीयू के लिए जारी निधियां (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	340	54.40
2	बिहार	307	49.12
3	छत्तीसगढ़	163	26.08
4	गोवा	2	0.20
5	गुजरात	127	8.89
6	हरियाणा	70	11.20
7	हिमाचल प्रदेश	44	7.04
8	झारखंड	236	37.76
9	कर्नाटक	275	44.00
10	केरल	29	4.64
11	मध्य प्रदेश	406	64.96
12	महाराष्ट्र	80	12.80
13	ओडिशा*	181	28.96
14	पंजाब	70	11.20
15	राजस्थान	536	85.76